

डॉ. आशुतोष उपाध्याय

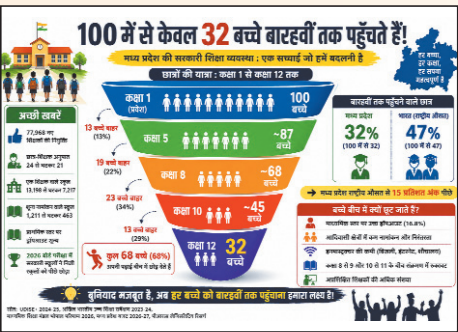
UDISE+ 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 1 लाख 22 हजार 120 स्कूल हैं, जिनमें से 92 हजार 250 सरकारी हैं। इन स्कूलों में 1 करोड़ 51 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और 7 लाख 17 हजार से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं.

जो अच्छा हुआ- सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षकों की भर्ती है. सिर्फ एक साल में प्रदेश ने 77 हजार 968 नए शिक्षक जोड़े. यह देश के किसी भी बड़े राज्य द्वारा एक साल में की गई सबसे बड़ी नियुक्ति है. इसका सीधा असर दिखा. छात्र-शिक्षक अनुपात 24 से घटकर 21 हो गया, जो देश के पाँच सबसे बड़े राज्यों में सबसे अच्छा है. राष्ट्रीय औसत 24 है. एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 13 हजार 198 से घटकर 7 हजार 917 रह गई. शून्य नामांकन वाले स्कूल 1 हजार 211 से घटकर मात्र 463 बचे. प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट अब शून्य है. लड़कियों का 0.0 प्रतिशत और लड़कों का 0.6 प्रतिशत. राष्ट्रीय औसत 0.3 प्रतिशत है. यह वास्तव में उल्लेखनीय है. सुविधाओं में भी प्रगति कई मामलों में देश से आगे है. 98.1 प्रतिशत स्कूलों में पुस्तकालय है, राष्ट्रीय औसत 89.5 प्रतिशत. खेल मैदान 94.9 प्रतिशत स्कूलों में, राष्ट्रीय औसत 83 प्रतिशत. दिव्यांग बच्चों के लिए 9.93 प्रतिशत स्कूलों में, राष्ट्रीय औसत 79.1 प्रतिशत. और सबसे उत्साहजनक बात, 2026 की बोर्ड परीक्षा में सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों को पीछे छोड़ दिया. दसवीं में सरकारी स्कूलों का परिणाम 76.80 प्रतिशत रहा और निजी स्कूलों का 68.64 प्रतिशत. 2022 में स्थिति उल्टी थी, तब सरकारी स्कूल 55.40

प्रतिशत पर थे और निजी 69.48 प्रतिशत पर. चार साल में यह बदलाव छोटा नहीं है. **जो चिंता का विषय है-** अब दूसरी तरफ देखिए. प्रदेश में कक्षा एक में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 32 बच्चे कक्षा बारहवीं तक पहुँच पाते हैं. राष्ट्रीय औसत 47 है. यह देश के सभी बड़े राज्यों में सबसे कम है. माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट 16.8 प्रतिशत है, राष्ट्रीय औसत 11.5 प्रतिशत. लड़कों में यह 18.9 प्रतिशत है और लड़कियों में 14.6 प्रतिशत. यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है. आमतौर पर माना जाता है कि लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ती हैं. मध्य प्रदेश में उल्टा हो रहा है. हर स्तर पर लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर है. दसवीं से ग्यारहवीं में जाने वाली लड़कियों 72.9 प्रतिशत हैं और लड़के 65.2 प्रतिशत. कन्या शिक्षा परिसर, केजीबीवी और छात्रवृत्ति योजनाओं का यह असर है. अब जरूरत लड़कों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की है. नामांकन के आँकड़े और भी गंभीर तस्वीर दिखाते हैं. प्राथमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन दर 63.9 प्रतिशत है, यानी 36 प्रतिशत बच्चे अपनी उम्र के अनुसार सही कक्षा में नहीं हैं. माध्यमिक स्तर पर यह दर 37.3 प्रतिशत है, यानी दस में से चार बच्चे भी सही कक्षा में नहीं हैं.

आदिवासी बच्चों का सवाल- यह प्रदेश की सबसे गंभीर समस्या है. मध्य प्रदेश में कुल छात्रों में 21.7 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं, जो किसी भी बड़े राज्य से अधिक है. पर उनकी स्थिति देखिए. देश भर में आदिवासी बच्चों का प्राथमिक नामांकन अनुपात 98.8 प्रतिशत है, मध्य प्रदेश में 78.9 प्रतिशत. माध्यमिक में राष्ट्रीय 81.3 प्रतिशत, प्रदेश में 58.6 प्रतिशत. और उच्चतर माध्यमिक में राष्ट्रीय 51.9 प्रतिशत के मुकाबले प्रदेश में केवल 32.8 प्रतिशत. आदिवासी लड़कों में तो यह आँकड़ा 29.7 प्रतिशत है. यानी ग्यारहवीं-बारहवीं की उम्र के दस में से तीन आदिवासी लड़के भी स्कूल में नहीं हैं. मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और शहडोल में स्थिति सबसे खराब है.

सुविधाओं का असली सच- औसत आँकड़े अच्छे दिखते हैं, पर जब सरकारी और निजी स्कूलों को अलग-



अलग देखा जाए तो असली तस्वीर सामने आती है. अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों में लगभग सभी बुनियादी सुविधाएँ 100 प्रतिशत हैं. सरकारी स्कूलों में नहीं. दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय सरकारी स्कूलों में केवल 13.7 प्रतिशत, अनुदान प्राप्त स्कूलों में 86.6 प्रतिशत. डिजिटल लाइब्रेरी सरकारी में 1 प्रतिशत, अनुदान प्राप्त में 49.1 प्रतिशत. लड़कियों के चालू शौचालय सरकारी में 86.8 प्रतिशत, बाकी सब जगह 100 प्रतिशत. चालू बिजली सरकारी स्कूलों में 85.4 प्रतिशत. बिजली की यह कमी सिर्फ बिजली की कमी नहीं है. जिस स्कूल में बिजली नहीं चलती, वहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट के आँकड़े कागजी रह जाते हैं. इंटरनेट प्रदेश के 45.7 प्रतिशत स्कूलों में है, राष्ट्रीय औसत 63.5 प्रतिशत. यह प्रदेश की सबसे बड़ी डिजिटल खाई है.

नई पहलों की समीक्षा- सरकार ने तीन बड़े कदम उठाए हैं. **संदीपनी विद्यालय-** पहले सीएम राहुल नाम था, अप्रैल 2025 में भगवान कृष्ण के गुरु आचार्य सान्दीपनि के नाम पर इनका नामकरण हुआ. इस समय 369 विद्यालय चल रहे हैं. इनमें स्मार्ट क्लास रूम, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, खेल सुविधाएँ और कला-संगीत के लिए अलग जगह है. परिणाम भी अच्छे हैं. 2026 की बोर्ड परीक्षा में दसवीं के 75.36 प्रतिशत और बारहवीं के 75.10 प्रतिशत छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए. 58 छात्र प्रदेश की मेरिट सूची में आए. बालाघाट के वारासिन्वनी के एक छात्र ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रतियोगिता 2026 में देश में

पहला स्थान पाया. पर एक बात साफ रहनी चाहिए. 369 विद्यालय प्रदेश के 92 हजार 250 सरकारी स्कूलों का मात्र 0.4 प्रतिशत हैं. घोषित लक्ष्य 9 हजार विद्यालयों का है, पर उस तक पहुँचने का बजट रास्ता अभी बजट दस्तावेजों में दिखाई नहीं देता.

पीएम कॉलेज ऑफ़ एक्सिलेंस- जुलाई 2024 में प्रदेश के सभी 55 जिलों में एक-एक ऐसा महाविद्यालय शुरू किया गया. हर कॉलेज में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र भी बनाया जा रहा है. मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है. उच्च शिक्षा में प्रदेश का नामांकन 27.7 लाख है, जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद देश में चौथे स्थान पर है. **पीएम श्री विद्यालय-** केंद्र की इस योजना को देश स्तर पर 2026-27 में लगभग 7 हजार 500 करोड़ रुपये मिले. पर चिंता की बात यह है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में इस योजना का खर्च कभी 60 प्रतिशत से ऊपर नहीं गया, जबकि सर्व-व्यापी समग्र शिक्षा योजना को केवल 50 करोड़ रुपये की मामूली बढ़ोतरी मिली.

ऑफ़ड्रॉ के अंतर- सरकार का दावा है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन 32.4 प्रतिशत बढ़ा है और 2025-26 में कुल नामांकन में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई. 2026-27 के लिए 1.45 करोड़ छात्रों का लक्ष्य रखा गया है. वहीं DISE+ के आँकड़े बताते हैं कि प्रदेश का कुल नामांकन 2021-22 के 1.62 करोड़ से घटकर 2024-25 में 1.52 करोड़ रह गया, यानी लगभग 10 लाख छात्र कम हुए. दोनों आँकड़े अलग-अलग अवधि और संभवतः अलग आधार के हैं. पर इतना बड़ा अंतर अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब शिक्षा विभाग को देना चाहिए.

शिक्षकों का प्रशिक्षण- संख्या बढ़ी, पर गुणवत्ता का सवाल बना हुआ है. माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक 79.5 प्रतिशत हैं, राष्ट्रीय औसत 92.7 प्रतिशत. यह बड़े राज्यों में सबसे कम है. पूर्व-प्राथमिक स्तर पर तो केवल 32.2 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षित हैं, राष्ट्रीय औसत 53.3 प्रतिशत. निपुण भारत के तहत बुनियादी साक्षरता के लक्ष्य इसी स्तर पर तय होते हैं. एक असामान्य बात यह भी है कि माध्यमिक स्तर पर पुरुष शिक्षक (77.8 प्रतिशत) महिला

अब क्या किया जाए

पहला- बचे हुए 7 हजार 217 एकल शिक्षक स्कूलों में दूसरा शिक्षक भेजा जाए. 78 हजार नए शिक्षक आए हैं, यह काम अब कठिन नहीं होना चाहिए. शुरुआत आदिवासी जिलों से हो. **दूसरा-** आदिवासी लड़कों के लिए आवासीय माध्यमिक विद्यालय. लड़कियों के लिए केजीबीवी का ढाँचा काम कर रहा है, आँकड़े इसकी गवाही देते हैं. लड़कों के लिए ऐसा कुछ नहीं है. सात सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाले जिलों में यह प्राथमिकता होनी चाहिए. **तीसरा-** सरकारी स्कूलों में शौचालय और बिजली का अभियान. दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय 13.7 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 40 प्रतिशत और लड़कियों के चालू शौचालय 95 प्रतिशत तक ले जाने का तीन साल का लक्ष्य तय हो. **चौथा-** बिजली और इंटरनेट. जिन 14.6 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में चालू बिजली नहीं है, वहाँ सौर ऊर्जा लगाई जाए. भारतनेट से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी दी जाए. **पाँचवाँ-** माध्यमिक शिक्षकों का अपात प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्राथमिकता में अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षक. **छठा.** कक्षा आठ से नौ और दस से ग्यारह के बीच का संक्रमण. यही वह जगह है जहाँ बच्चे सबसे ज्यादा छूटते हैं. आठवीं से नौवीं में जाने की दर 77.8 प्रतिशत है, राष्ट्रीय औसत 86.6 प्रतिशत. यह अकेला आँकड़ा प्रदेश की सबसे कमजोर कड़ी बताता है.

शिक्षकों (81.6 प्रतिशत) से कम प्रशिक्षित हैं. देश में आमतौर पर उल्टा होता है. **चुनौती-** मध्य प्रदेश ने पिछले चार सालों में जो किया, वह हल्के में लेने लायक नहीं है. शिक्षक आ गए, प्राथमिक ड्रॉप आउट खत्म हो गया, सरकारी स्कूलों के बोर्ड परिणाम निजी स्कूलों से बेहतर हो गए. ये असली उपलब्धियाँ हैं. पर अब चुनौती अलग है. समस्या अब शिक्षक की कमी नहीं है, न ही स्कूल भवन की. समस्या यह है कि बच्चा नौवीं-दसवीं तक आते-आते कहीं छो जाता है. 100 में से 68 बच्चे बारहवीं तक नहीं पहुँचते.

दिल्ली की म्यूजिकल चेयर रेस

वेयर रेस नामक खेल से शायद सब ही न केवल परिचित ही होंगे बल्कि अपनी स्कूलिंग के दौरान बचपन में वे इस खेल के प्रतिभागी भी रह चुके होंगे. यह क्या शानदार खेल है. इस खेल को म्यूजिकल चेयर रेस के नाम से भी जाना जाता है. अन्य खेलों के समान इसमें भी प्रतिस्पर्धा और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलता है. इस खेल में सभी प्रतिभागियों की गिनाई उस कुर्सी पर लगी रहती है उसे जिस पर कब्जा जमाना होता है.

जिसने उस पर कब्जा जमा लिया कुर्सी उसी की हो जाती थी. बचपन में कुर्सी रेस, खोखो और कबड्डी का खेल स्कूली जीवन के लोकप्रिय खेलों में शुमार थे. बड़े होने पर भले ही ये खेल हम से छूट जाते हों. पर सियासत में आज भी इन खेलों का गजब का क्रैज है. सभी नेता इस रेस में शुमार हैं.

जिन लोगों ने अपने वाइल्ड हुड में ये खेल नहीं खेले या देखे हों उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है. वे इसका आनंद इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉंक्रिट जनता पार्टी के धरने के दौरान वहां चल रही म्यूजिकल चेयर रेस को देख कर ले सकते हैं. जैसे कहावत है सब का मौलिक एक देस ही सियासत में सब का एक ही लक्ष है 7- लोक कल्याण मार्ग का बंगला. लखनऊ वाले भाई ने इसके लिए जंतर मंतर पर अनुष्ठान किया तो शांडिल्य गोत्र धारी सीधे बिना ब्रेक लगाए रेस करते हुए पुराने 7 सेक कोर्स रोड पर जा कर धमक गए.

वहां मौजूद चौकीदारों ने कहा- ऐ थामा थामा, बाबा कहाँ घुसे आ रहे हो ? ये घर अभी खाली नहीं हुआ है. खबर मिली तो टूट्टी वाले ने मन ही मन कहा पार्टीनर से दगा ! इट्स अ टू मच. भैया भी नंगे पैर जंतर मंतर छोड़, दौड़ लगा वहां पहुँच गए और बुदबुदाने लगे अछा सिला दिया तूने मेरे पुलिस बल ने दोनों को सड़क से टंगाटोली कर 25 लाख की बस में डाल कर रवाना किया. ये है दिल्ली की चुनौती म्यूजिकल चेयर रेस. केजरीवाल पहले से ही जंतर मंतर पर झंडा गाड़े बैठे हैं. कुल मिला कर सब गा रहे हैं मौका मौका.

उत्तर कोरिया, चीन और रूस ने बदल दिया ईरान का सैन्य भूगोल

जॉर्डन में अल-अज़क़ एयरबेस, प्रिंस हसन एयरबेस, किंग फैसल एयरबेस और अल-सफावी बेस जैसे अमेरिकी और अन्य रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान अब केवल मिसाइलों या ड्रोन के सीमित उपयोग तक ही नहीं रुका है, बल्कि वह अपने सैन्य अभियानों में बहुस्तरीय और समन्वित रणनीतियों का प्रयोग कर रहा है। यह घटनाक्रम आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति का एक महत्वपूर्ण संकेत है. आज किसी संघर्ष की सफलता केवल हथियारों की संख्या या उनकी मारक क्षमता से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से भी निर्धारित होती है कि विभिन्न सैन्य साधनों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर क्षमताओं, ड्रोन, मिसाइलों और खुफिया तंत्र का कितनी प्रभावी ढंग से समन्वय किया जाता है. यही कारण है कि हाइब्रिड वॉरफेयर और मल्टी-लेयर्ड अटैक जैसे अवधारणाएँ आधुनिक युद्ध की केंद्रीय रणनीति बनती जा रही हैं.

दरअसल पश्चिम एशिया में हाल के वर्षों में यह किसी देश की सैन्य क्षमता ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है, तो वह ईरान है. कभी हथियारों और सैन्य तकनीक के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहने वाला यह देश आज लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, अत्याधुनिक ड्रोन, आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता के कारण क्षेत्र की सबसे प्रभावशाली सैन्य शक्तियों में गिना जाता है. जॉर्डन में हमलों में जिस रणनीति का प्रदर्शन हुआ, उसे सैन्य विशेषज्ञ मल्टी-लेयर्ड अटैक कहते हैं. इस रणनीति के तहत सबसे पहले बड़ी संख्या में आत्मघाती ड्रोन और कम लागत वाले हवाई प्लेटफॉर्म छोड़े जाते हैं. इनका उद्देश्य विरोधी देश के रडार और वायु रक्षा प्रणाली को व्यस्त रखना होता है.

इसके बाद लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से कमांड सेंटर, एयरबेस, विमान हेंगर और अन्य रणनीतिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता है. मिसाइल और ड्रोन का यह संयुक्त उपयोग पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि उन्हें एक साथ अनेक दिशाओं से आने वाले अलग-अलग प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है. यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ. इसके पीछे लगभग तीन दशकों का सैन्य, तकनीकी और औद्योगिक विकास छिपा है. इस विकास में ईरान के स्वदेशी अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन उनका ही बड़ा योगदान चीन, उत्तर कोरिया और रूस के साथ

जैसे मिसाइलें उपलब्ध कराईं. बाद में इन्हीं तकनीकों के आधार पर ईरान ने शाहाब-1, शाहाब-2 और शाहाब-3 जैसी मिसाइलों का विकास किया. उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल तकनीक ने ईरान की मध्यम दूरी की मिसाइल क्षमता को नई दिशा दी. इसके अतिरिक्त मिसाइल इंजन, प्रक्षेपण प्रणाली, मोबाइल लॉन्चर, उत्पादन तकनीक, परीक्षण प्रक्रियाएँ और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर कोरिया का सहयोग महत्वपूर्ण माना जाता है. समय के साथ ईरान ने इन तकनीकों को केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने अनुसंधान और उत्पादन क्षमता के अनुरूप विकसित भी किया. परिणामस्वरूप आज उसकी कई मिसाइलें मूल उत्तर कोरियाई डिजाइनों से काफी आगे निकल चुकी हैं. रूस का योगदान मुख्य रूप से वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अंतरिक्ष तकनीक और सामरिक सहयोग के क्षेत्र में दिखाई देता है. रूस ने ईरान को रू-300 जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, रडार तकनीक, हेलीकॉप्टर, उपग्रह सहयोग और आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क विकसित करने में सहायता दी.

ईरान के शाहदे ड्रोन कार्यक्रम के विकास में भी चीनी औद्योगिक अनुभव और वाणिज्यिक सहयोग ने ईरान को रक्षा उद्योग को तकनीकी आधार दिया, तो उत्तर कोरिया ने उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की बुनियाद रखी. 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने ईरान को स्कड-बी और स्कड-सी जैसी मिसाइलें उपलब्ध कराईं. बाद में इन्हीं तकनीकों के आधार पर ईरान ने शाहाब-1, शाहाब-2 और शाहाब-3 जैसी मिसाइलों का विकास किया. उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल तकनीक ने ईरान की मध्यम दूरी की मिसाइल क्षमता को नई दिशा दी. इसके अतिरिक्त मिसाइल इंजन, प्रक्षेपण प्रणाली, मोबाइल लॉन्चर, उत्पादन तकनीक, परीक्षण प्रक्रियाएँ और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर कोरिया का सहयोग महत्वपूर्ण माना जाता है. समय के साथ ईरान ने इन तकनीकों को केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने अनुसंधान और उत्पादन क्षमता के अनुरूप विकसित भी किया. परिणामस्वरूप आज उसकी कई मिसाइलें मूल उत्तर कोरियाई डिजाइनों से काफी आगे निकल चुकी हैं. रूस का योगदान मुख्य रूप से वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अंतरिक्ष तकनीक और सामरिक सहयोग के क्षेत्र में दिखाई देता है. रूस ने ईरान को रू-300 जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, रडार तकनीक, हेलीकॉप्टर, उपग्रह सहयोग और आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क विकसित करने में सहायता दी.

ईरान के शाहदे ड्रोन कार्यक्रम के विकास में भी चीनी औद्योगिक अनुभव और वाणिज्यिक सहयोग ने ईरान को रक्षा उद्योग को तकनीकी आधार दिया, तो उत्तर कोरिया ने उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की बुनियाद रखी. 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने ईरान को स्कड-बी और स्कड-सी जैसी मिसाइलें उपलब्ध कराईं. बाद में इन्हीं तकनीकों के आधार पर ईरान ने शाहाब-1, शाहाब-2 और शाहाब-3 जैसी मिसाइलों का विकास किया. उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल तकनीक ने ईरान की मध्यम दूरी की मिसाइल क्षमता को नई दिशा दी. इसके अतिरिक्त मिसाइल इंजन, प्रक्षेपण प्रणाली, मोबाइल लॉन्चर, उत्पादन तकनीक, परीक्षण प्रक्रियाएँ और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर कोरिया का सहयोग महत्वपूर्ण माना जाता है. समय के साथ ईरान ने इन तकनीकों को केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने अनुसंधान और उत्पादन क्षमता के अनुरूप विकसित भी किया. परिणामस्वरूप आज उसकी कई मिसाइलें मूल उत्तर कोरियाई डिजाइनों से काफी आगे निकल चुकी हैं. रूस का योगदान मुख्य रूप से वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अंतरिक्ष तकनीक और सामरिक सहयोग के क्षेत्र में दिखाई देता है. रूस ने ईरान को रू-300 जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, रडार तकनीक, हेलीकॉप्टर, उपग्रह सहयोग और आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क विकसित करने में सहायता दी.

ईरान के शाहदे ड्रोन कार्यक्रम के विकास में भी चीनी औद्योगिक अनुभव और वाणिज्यिक सहयोग ने ईरान को रक्षा उद्योग को तकनीकी आधार दिया, तो उत्तर कोरिया ने उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की बुनियाद रखी. 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने ईरान को स्कड-बी और स्कड-सी जैसी मिसाइलें उपलब्ध कराईं. बाद में इन्हीं तकनीकों के आधार पर ईरान ने शाहाब-1, शाहाब-2 और शाहाब-3 जैसी मिसाइलों का विकास किया. उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल तकनीक ने ईरान की मध्यम दूरी की मिसाइल क्षमता को नई दिशा दी. इसके अतिरिक्त मिसाइल इंजन, प्रक्षेपण प्रणाली, मोबाइल लॉन्चर, उत्पादन तकनीक, परीक्षण प्रक्रियाएँ और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर कोरिया का सहयोग महत्वपूर्ण माना जाता है. समय के साथ ईरान ने इन तकनीकों को केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने अनुसंधान और उत्पादन क्षमता के अनुरूप विकसित भी किया. परिणामस्वरूप आज उसकी कई मिसाइलें मूल उत्तर कोरियाई डिजाइनों से काफी आगे निकल चुकी हैं. रूस का योगदान मुख्य रूप से वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अंतरिक्ष तकनीक और सामरिक सहयोग के क्षेत्र में दिखाई देता है. रूस ने ईरान को रू-300 जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, रडार तकनीक, हेलीकॉप्टर, उपग्रह सहयोग और आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क विकसित करने में सहायता दी.

आज की भारतीय महिला केवल परिवार की धुरी ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की सशक्त आधारशिला भी है। वह घर, परिवार, कार्यस्थल और सामाजिक दायित्वों के बीच निरंतर संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है. बदलती जीवनशैली, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, समय का अभाव और अनेक अपेक्षाओं के बीच मानसिक एवं भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आज प्रत्येक महिला के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. ऐसे समय में समायोजन की क्षमता ही उसे तनावमुक्त, आत्मविश्वासी और सफल जीवन की ओर अग्रसर करती है.

समायोजन का अर्थ केवल परिस्थितियों से समझौता करना नहीं है, बल्कि स्वयं को इस प्रकार विकसित करना है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रख सके. योग इसी समायोजन क्षमता को विकसित करने का एक वैज्ञानिक, व्यावहारिक और प्रभावशाली माध्यम है. योग भारतीय

संस्कृति की अमूल्य धरोहर है. यह केवल शरीर को स्वस्थ रखने का अभ्यास नहीं, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के मध्य संतुलन स्थापित करने की संपूर्ण जीवन-पद्धति है. नियमित योगाभ्यास से मन शांत होता है, तनाव कम होता है, भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है तथा व्यक्ति में धैर्य, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण का विकास होता है. यही गुण महिलाओं को परिवार, समाज और कार्यस्थल पर बेहतर समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं.

कार्यरत महिलाओं पर योग का प्रभाव- कार्यरत महिलाओं को कार्यालय की जिम्मेदारियों के साथ-साथ परिवार, बच्चों तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है. दोहरी जिम्मेदारियों के कारण उनमें तनाव, थकाऊ, अनिद्रा, चिंता और भावनात्मक दबाव की संभावना अधिक रहती है. नियमित योग, प्राणायाम एवं ध्यान से तनाव हार्मोन कम होते हैं, कार्यक्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है तथा मानसिक संतुलन बना रहता है. परिणामस्वरूप वे अपने कार्यस्थल और परिवार दोनों में

सफलतापूर्वक समायोजन स्थापित कर पाती हैं. **गैर-कार्यरत महिलाओं पर योग का प्रभाव-** अक्सर यह माना जाता है कि गृहिणियों का जीवन अपेक्षाकृत सरल होता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है. घरेलू कार्यों का निरंतर दबाव, परिवार के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी, स्वयं के लिए समय का अभाव तथा भावनात्मक अपेक्षाएँ उन्हें भी मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं. योगाभ्यास उनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा, आत्मसम्मान, धैर्य और मानसिक शांति का विकास करता है. इससे उनका पारिवारिक वातावरण अधिक सुखद, संतुलित और सौहार्दपूर्ण बनता है. **तुलनात्मक अध्ययन:-** कार्यरत एवं गैर-कार्यरत महिलाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नियमित योगाभ्यास करने वाली दोनों श्रेणियों की महिलाओं में समायोजन क्षमता, तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन का स्तर अधिक पाया जाता है. कार्यरत महिलाओं में योग का प्रभाव मुख्यतः कार्यक्षमता, समय प्रबंधन, मानसिक दृढ़ता एवं निर्णय क्षमता पर अधिक दिखाई देता है,



छात्र आंदोलन का इतिहास

प्राचीन भारत से लेकर अगर हम छात्र आंदोलन का इतिहास देखें तो हमें भारत की आजादी का प्रथम आंदोलन को 1857 में हुआ था, उसके बीच तक कहीं भी कोई छात्र आंदोलन का इतिहास नहीं मिलता है, उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन में राजा लड़े थे उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र भी थे! गुरु का सम्मान प्राचीन भारत में होता था और जो शासक थे वो गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करते थे, सुदामा और कृष्णा की मित्रता इसका उदाहरण है! यह भी एक कारण रहा प्राचीन भारत में छात्र कभी भी उत्तेजित नहीं हुए क्योंकि उन्हें गुरु अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखते थे! मुगल शासन में और अंग्रेजों के शासन काल में केवल प्रतिष्ठित परिवार के लोगों को ही शिक्षा का अधिकार था और आंबेडकर जी जैसे कई नेताओं को सभी को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था तब देश की आजादी के बाद शिक्षा का अधिकार स्वतंत्र भारत में संविधान के अंतर्गत, सबको दिया गया! 1970 के दशक में जय प्रकाश जी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था इमरजेंसी के बाद जो कांग्रेस सरकार के विरुद्ध था और वह एक सकारात्मक आंदोलन था और चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई थी,परन्तु वो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन लाना चाहते थे नहीं का पाए क्योंकि जनता पार्टी टूट गई और उनके टूटने के बाद कई दल और बन गए और शिक्षा की स्थिति नहीं सुधार पाई !शने: शने: हमने देखा कि गुरु का सम्मान छात्रों द्वारा कम होने लगा, क्या कारण रहे ? मैं उसमें नहीं जानता ,परन्तु ऐसा होता रहा और जो शासन में थे ,उन्होंने छात्रों का राजनीतिक उपयोग करना शुरू कर दिया जिसके कारण गुरु और शिष्य के बीच का जो अटूट संबंध था वो कमजोर होता चला